an>

Title: Discussion on points arising out of the answer given by the Minister of Agriculture on 05.08.2014 to Starred Question No. 383 regarding "Rise in Prices of Milk" .

श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही) : सभापति जी, बहुत गौरव की बात है कि भारत की संसद में देवपूजित भोज्य पदार्थ दूध के बारे में चर्चा शुरू हो रही है। पिछले दिनों दूध के दाम में वृद्धि के बारे में एक सवाल आया था, जो अधूरा रह गया था। मैं समझता हूं कि आज की चर्चा उसी संदर्भ में है। यह देश बहुत प्राचीन है और इसका प्राचीनता का इतिहास है। हमारे देश के ऋषियों ने दूध को इस देश की परम्परा, संस्कृति और सभ्यता से जोड़ कर रखा है। ...(व्यवधान) दूध केवल व्यापार का ही भोज्य पदार्थ नहीं होता। दूध का संबंध इस देश की सभ्यता, परम्परा और संस्कृति के भोज्य पदार्थों से भी है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, प्राचीन काल से ऋषियों ने उत्तम भोज्य के तौर पर दूध को निर्देशित किया है। आज भी हमारे देश के बहुसंख्यक लोग दूध पीते हैं और उसके कारण बलिष्ठ होते हैं। दूध इस देश के जरूरी भोज्य पदार्थ में आता है। दूध के दाम में वृद्धि के विषय में पिछले दिनों भी चर्चा हुई थी। एक किसान होने के नाते मुझे चिंता होती है कि कृषि में उत्पादित होने वाली चीजों का जब दाम बढ़ता है तो देश में हल्ला मच जाता है, चाहे खेत में उत्पादित होने वाला अनाज हो या किसान द्वारा पैदा किये जाने वाली चीजें हों। जब भी उनके दाम बढ़ते हैं तो देश में महंगाई का हल्ला मच जाता है।

सभापति जी, मुझे चिंता तब होती है जब कारखाने में बनने वाला सामान, जिसे किसान उपभोग में लाता है, चाहे वह कपड़ा, कागज, बिजली, पानी, दवाई आदि हो, ये सब चीजें जब महंगी होती हैं, तो कानों-कान खबर नहीं होती। लेकिन किसान द्वारा उत्पादित की जाने वाली चीजें जब महंगी होती हैं तो देश में महंगाई का हल्ला मच जाता है और लोग कहते हैं कि सरकार महंगाई क्यों नहीं रोक पाती? मैं इस बात को बहुत चिंतापूर्वक कह सकता हूं कि दाम तय करना हो, तो संसद सर्वसम्मत से दाम तय कर ले कि कृषि में जो लागत होती है, उस लागत पर क्या लाभ होगा और कारखाने में बनने वाली चीजों पर जो लागत होती है, उस पर क्या लाभ होगा? मैं समझता हूं कि संसद इसे सर्वसम्मत से तय कर सकती है, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की होती है कि जब खेती में पैदा होने वाली चीजों का दाम बढ़ता है, तो सब लोग माथा पीटकर कहने लगते हैं कि दूध, गेहूं, दाल, सब्जी आदि के दाम बढ़ गये।

लेकिन चिन्ता इस बात की है कि जो परिश्रम के पसीने से खेत में पैदा करता है, उसको उसका लाभ नहीं मिलता है। सदन में यह कानून बनना चाहिए कि जो परिश्रम के पसीने से खेती में पैदा करता है, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। जहाँ तक दूध की बात है, अपने देश में 37 करोड़ लीटर रोज़ दूध पैदा होता है। 125 करोड़ की आबादी में 37 करोड़ लीटर दूध होता है। दूध की कितनी खपत है? एक आदमी को कितने दूध की जरूरत है? इस बात को भी हम प्रामाणिकता से कह सकते हैं कि 37 करोड़ लीटर दूध में देश की 125 करोड़ आबादी को दूध उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसका कारण है। इसका कारण यह है कि दुधारू पशुओं को भारी मात्रा में कटान के लिए भेजा जाता है। देश से भारी मात्रा में मांस निर्यात होता है। भैंसों के दूध हमें आज भी इसलिए कम उपलब्ध होते हैं क्योंकि भैंसों के मांस की उपयोगिता कई देशों में है। हमारे देश से भैंसों का निर्यात उसे काटने के लिए हो रहा है। यह बात सरकार की जानकारी में होनी चाहिए और इस पर रोक लगायी जानी चाहिए। एक किसान होने के नाते मैं यह बात कह सकता हूँ, लेकिन इस बात को बहुत-से लोग नहीं समझते हैं। बहुत-से लोग इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि वे दूध का उत्पादन नहीं करते हैं, बहुत-से लोग इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि वे खेती के बारे में नहीं जानते हैं, बहुत-से लोग इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि वे खेत में परिश्रम की कीमत नहीं समझते हैं, लेकिन हम इस बात को जानते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वे सभी लोग इस बात को जानते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि यह कृषि और ऋषि परम्परा का देश है क्योंकि ऋषियों ने हमें वैदिक काल में बताया था कि कहाँ किस तरह की खेती होनी चाहिए। वैदिक काल में हमें ऋषियों ने बताया था कि गाय और भैंस का दूध पीने वाले लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं।

सभापति जी, आज भी हमारे देश में गंगा-यमुना के मैदान में खेती की बहुत बड़ी संभावना है। प्लानिंग कमिशन की रिपोर्ट देख लीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन गंगा-यमुना और घाघरा का मैदान है। उस उपजाऊ जमीन में केवल अनाज ही नहीं पैदा होता है, बल्कि दूध की भी भारी मात्रा में उत्पादन होने की संभावना है। यदि दूध का उत्पादन होगा, तो गंगा-यमुना के मैदान में पैदा होने वाले अनाज और दूध से हम दुनिया का पेट भर सकते हैं। यह मैं नहीं कहता हूँ, प्लानिंग कमिशन की रिपोर्ट को देखकर आप समझ सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। श्री महेन्द्र जी यहाँ पर बैठे हैं, वे चन्दौली से सांसद हैं, वे भी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। श्री मालवीय जी कहते थे- " ग्रामे-ग्रामे पाठशाला, व्यायामशाला गृहे-गृहे। " गाँव-गाँव में पाठशाला होनी चाहिए और घर-घर में व्यायामशाला होनी चाहिए। इस अवधारणा के आधार पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। वहाँ कुलपति कौन होता था? जो दस हजार छात्रों को शिक्षा देता था, हजारों गाय रखता था, छात्रों को दूध पिलाता था, उन्हें बलिष्ठ बनाता था, वह कुलपति होता था। आज के जैसे कुलपति नहीं होते थे कि कोई सत्तारूढ़ पार्टी होगी, तो उसके सांसदों के सामने परिक्रमा करेंगे और कुलपति की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। हम काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, कुलपति को गुरुजी कहते रहे हैं। आज बाजारीकरण ने हमारे देश की सारी परिस्थितियों पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। जिसने देश की परिस्थितियों पर प्रश्नचिह्न लगाया है, वह बाजारीकरण है। बाजारीकरण ने ही हमारे देश को मांस के निर्यात के लिए विवश किया है। हमारे देश में, गंगा के किनारे रहने वाले लोग, नदियों के किनारे रहने वाले लोग, आज भी सम्मान के साथ इस बात को कहते हैं कि हम दूध पीकर अपना जीवनयापन कर सकते हैं। जहाँ तक दूध के दाम की बात है, तो दूध के दाम बढ़ते कैसे हैं? दूध के दाम आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के बाद बढ़ते हैं। सहकारी संस्थाएँ टूट गयीं और उस पर निजी कंपनियों का कब्जा हो गया, ये 40-50 रुपए किलो दूध लोगों को बेचते हैं और जो किसान दूध का उत्पादन करता है, उससे वे 20-25 रुपए किलो दूध खरीदते हैं। यह कानून बनना चाहिए। हमारे कृषिमंत्री जी यहां बैठे हैं, जब खेती के उत्पादन के दाम की बात आती है, तो चाहे इधर बैठे हुए लोग हों, चाहे उधर बैठे हुए लोग हों।...(व्यवधान) सभापति जी, यह बात विस्तार से होनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि इस बात को आपको सुनना भी चाहिए।

HON. CHAIRPERSON : This is half an hour discussion.

श्री वीरेन्द्र सिंह :यह दूध का विषय है। जब दाम तय करने की बात आती है, तो कहा जाता है कि उचित मूल्य मिलेगा, समर्थन मूल्य मिलेगा। मैं भी किसान हूं, आज तक मैं इस उचित मूल्य और समर्थन मूल्य की परिभाषा नहीं समझ पाया कि उचित मूल्य क्या होता है और समर्थन मूल्य क्या होता है। आप क्यों नहीं "लाभकारी" शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि खेती के उत्पादों में, चाहे दूध हो, चाहे अनाज हो, सब्जी हो, फल हो, हर चीज की लाभकारी कीमत देंगे और लाभकारी कीमत के लिए सदन में कानून बनाएंगे।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You ask the question that you want to ask.

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति जी, मेरी बात सुन लीजिए। आप घण्टी बजाते हैं, वह आपका अधिकार है, लेकिन अपनी बात कहने का मेरा अधिकार है। ...(व्यवधान) आप यदि चाहें तो उसे रिकॉर्ड से बाहर निकाल दीजिएगा, लेकिन मुझे अपनी बात कहनी है।...(व्यवधान)

उसको लाभकारी कीमत बनाने के लिए कानून बना लीजिए। मैं समझता हूं कि पूरा सदन सर्वसम्मति से लाभकारी कीमत देने के लिए कानून बनाने पर सहमत हो सकता है। किसान को जब 20 रुपये प्रति किलो दूध बेचना पड़ता है और उसी को जब खरीदना होता है, तब 40 रूपये प्रति किलो खरीदना पड़ता है, यह देश में किसकी व्यवस्था हो सकती है और कौन इसकी व्यवस्था करेगा? इसलिए मैं कह सकता हूं कि दूध के निर्यात की बात अपने देश में होनी चाहिए। बगल के देशों मे दूध का अभाव है, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान पहले सबसे बड़ा उत्पादक देश था, बांग्लादेश में दूध का अभाव है। हम दूध के उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं, दूसरे देश में निर्यात कर सकते हैं और अपने देश की जनता को दूध उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन सवाल एक ही है कि दूध उत्पादन करने वाले किसानों को लाभकारी कीमत मिले, समर्थन मूल्य और उचित मूल्य जैसे शब्द सदन में न प्रयोग हो, यही मेरा निवेदन है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, हमारे बहुत से साथी बैठे हैं, बृजभूषण जी हैं, महेन्द्र जी हैं।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You have already completed.

Shri Rajeev Satav.

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति जी, लोग कहते हैं कि अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं, मैं कहना चाहता हूं कि दूध सपूदाय के लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं।...(व्यवधान) लोगों के लिए अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हम लोग दूध सपूदाय के लोग हैं।...(व्यवधान) मैं यही बात कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ सांसद ने अच्छे दिनों की बात की, मैं उसी बात से शुरूआत करते हुए कहना चाहता हूं कि विश्व में अगर कहीं सबसे ज्यादा पशु हैं, तो भारतवर्ष में हैं, लेकिन दूध इंडस्ट्री पर जिस प्रकार से ध्यान देने की जरूरत है, सरकार ने उस प्रकार से ध्यान अभी तक नहीं दिया है। ...(व्यवधान) आम ग्रामीण युवा इसकी ओर इसलिए नहीं बढ़ना चाह रहा है क्योंकि इसके लिए जो इंसेंटिव और सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, वह इंसेंटिव और सब्सिडी नहीं मिल रही है। मेरा आग्रह है कि युवाओं को 50 प्रतिशत से ज्यादा रोजगार दूध इंडस्ट्री से मिल सकता है। ...(व्यवधान) जो युवा रोजगार मांगेगा, क्या उसको बैंक कर्ज देगी और उस पर सब्सिडी में बढ़ोतरी सरकार द्वारा दी जाएगी? यही मैं सरकार से जानना चाहता हूं।

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज) : सभापति महोदय, कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कम्बल भीगे पानी। पानी का दाम और दूध का दाम बराबर है, बल्कि पानी का दाम ज्यादा है। जो लोग दूध खरीदते हैं, उनका दूध सस्ता पड़ता है और जो लोग दूध का उत्पादन करते हैं, उनका दूध महंगा पड़ता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माना है। लगभग 70 प्रतिशत नकली दूध बाजार में बिक रहा है। "टाइम्स ऑफ इंडिया" समाचार पत्र में दूध पर हुए सर्वे पर यह खबर छपी कि बाजार में 76 प्रतिशत दूध मिलावटी है। आज हम दूध उत्पादन के क्षेत्र में अपने आपको भले ही गौरवान्वित महसूस करते हों, लेकिन यह जो 70 प्रतिशत और 76 प्रतिशत कि रिपोर्ट है, अगर इस नकली दूध को मार्केट से निकाल दें तो क्या स्थिति होगी, यह आप समझ सकते हैं। आज इसी कारण नकली दूध, नकली पनीर, नकली घी बाजार में बिक रहा है। आज कोई भी व्यक्ति पनीर और घी पर विश्वास नहीं कर सकता। हमारे गांव के किसानों के लड़के शहरों में 3,000 रुपए के लिए रिक्शा चलाने के लिए तैयार हैं। माननीय वीरेन्द्र सिंह जी ने जो सवाल खड़ा किया कि जो हमारी लागत है, क्या इस पर आप सब्सिडी देंगे, क्योंकि खरीदना सस्ता है और पैदा करना महंगा है, इस बात से पूरा सदन सहमत है। इसलिए मंत्री जी बताएं कि क्या वह सब्सिडी देंगे? मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दूध का अगर आप उचित मूल्य दे दें, लाभकारी मूल्य दे दें, तो गांवों के नौजवानों की बेरोजगारी दूर हो सकती है। क्या इस दिशा में सरकार कुछ काम करेगी?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर): सभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान की। मैं वीरेन्द्र सिंह जी और अन्य सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस अत्यावश्यक विषय को चर्चा के लिए सदन में रखा। भारत विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। आज की तारीख में हमारे यहां 100 मिलियन टन से ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। यदि इस दूध के मूल्य की बात की जाए तो देश में जितना गेहूं या चावल का कुल उत्पादन होता है, उसके समग्र मूल्य से ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। जिस तरह की आवश्यकता वर्तमान में दूध की इस देश में है, जैसे आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 2022 तक हमारी यह मांग 100 मिलियन टन से बढ़कर 180 मिलियन टन हो जाएगी। इतनी चिंताजनक स्थिति देश में होने वाली है कि अगले 15 साल में प्रति वर्ष पांच मिलियन टन से ज्यादा की वृद्धि दूध उत्पादन में करनी पड़ेगी। यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि जहां एक ओर विश्व में दूध की कीमत गिर रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश में बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि इस उद्योग को, इस व्यवस्था को सरकार की ओर से जिस तरह का संरक्षण दिया जाना चाहिए, जिस तरह का संरक्षण पशुपालकों को दिया जाना चाहिए, जिस तरह की ऋण सुविधा उन्हें दी जानी चाहिए, वह नहीं दी जा रही है। चारे का उत्पादन यदि कोआपरेटिव सेक्टर में नहीं किया जाएगा, यदि ऑयलकेक का और पशु आहार का उत्पादन नहीं किया जाएगा, यदि पशु बीमा को ढंग से लागू नहीं किया जाएगा, तो निश्चित रूप से देश में दूध की कमी बहुत अधिक बढ़ने वाली है। इसके साथ ही यह जो कीमत बढ़ रही है, किसान या पशुपालक को इसका जो फायदा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है, इससे स्थिति और अधिक गम्भीर होने वाली है। इसलिए सरकार इस विषय में निश्चित रूप से चिंता करे, इस बात मैं सरकार से आग्रह करता हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र): सभापति जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर हो रही चर्चा में प्रश्न पूछने का मौका दिया।

श्री बृजभूषण शरण सिंह : हम लोग चिंतित थे कि सब राजपूत बोल रहे हैं, लेकिन बहुत खुशी हुई कि यादव भी बोल रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं।

श्री राम कृपाल यादव : मेरा सौभाग्य है कि मैं एक दूध बेचने वाले का बेटा हूं। मेरा खानदानी पेशा दूध बेचने का है। आज भी हमारे घर में दूध बेचा जाता है। उसके दर्द को और पीड़ा को किसान श्री वीरेन्द्र सिंह जानते हैं, उनसे कहीं अधिक एक दूध बेचने वाला जानता है।

जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि हम में दूध उत्पादन करने की क्षमता है और हम दूध का उत्पादन कर भी रहे हैं। पहले कहा जाता था कि डेनमार्क में दूध की नदियां बहती हैं, मगर अब भारत में दूध की नदियां बह रही हैं लेकिन दूध का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। गौ-पालकों में निराशा का भाव आ रहा है और गौ-पालक दूध बेचने का व्यवसाय बंद करते जा रहे हैं। चारे की कीमत, दाने की कीमत और मजदूरी की कीमत बढ़ती जा रही है। सभापति जी, आप भी किसान परिवार से आते होंगे और आपने देखा होगा कि सवेरे-सवेरे गौ-पालक उठता है और 11 से 12 बजे तक मेहनत करके दूध बेचता है लेकिन उस दूध की कीमत क्या है? हमारे मित्र ने सही कहा और मैं अपनी पीड़ा यहां व्यक्त कर रहा हूं, मैं खुद दूध बेचने वाले परिवार से आता हूं। करोड़ों लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं और इसी से अपना पेट पालते हैं। आप शहरों में देखिये, गौ-पालक देहात से आकर खुले आकाश में रहते हैं, उन्हें पुलिस की प्रताड़ना सहनी पड़ती है, इसके बावजूद वे दूध के रूप में अमृत पिलाने का कार्य करते हैं। गाय-भैंस की कीमत बढ़ती जा रही है लेकिन उसकी एवज में क्या दूध की कीमत बढ़ाई जा रही है? पानी ज्यादा कीमत पर बोतल में मिल रहा है, शराब की कीमत बढ़ रही है और दूध जिससे हम मजबूत बनते हैं उसकी कीमत नहीं बढ़ रही है।

HON. CHAIRPERSON : You may ask a question. Please put a question. What do you want to ask?

...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please take your seats.

...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please take your seats. This is Half-an-Hour discussion. The hon. Member has already explained everything. Four other hon. Members are allowed to put further questions. They have already put their questions.

Now, the hon. Minister has to reply.

...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: That is all. You put your question. What do you want?

...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Okay, you put your question now. What is the question?

श्री राम कृपाल यादव : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप गौ-पालकों के लिए कौन से ऐसे उपाय कर रहे हैं जिससे उनकी इस व्यवसाय के प्रति जो मनोवृति घटती जा रही है उस पर लगाम लगे। साथ ही क्योंकि उन्हें दूध की कीमत नहीं मिलती है, उन्हें संरक्षण देने का आप कौनसा उपाय कर रहे हैं, मैं केवल यही प्रश्न पूछना चाहता हूं।

...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: That is why, we have taken up the Half-an-Hour discussion.

...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record, except what the hon. Minister says.

*(Interruptions) â€¦**

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, please start your reply and address the Chair.

...(*Interruptions*)

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : महोदय, पांच अगस्त के प्रश्न संख्या 383 के उत्तर से उत्पन्न तीन मुख्य बातों के लिए सूचना माननीय सदस्य वीरेन्द्र जी के द्वारा दी गयी थी। उसके अलावा भी माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें विस्तार से रखी हैं। मैं निश्चित रूप से माननीय वीरेन्द्र जी को और बाकी जिन सदस्यों ने अपनी राय दी है, बताना चाहता हूं कि तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। उसमें पहला विषय था, पशुओं की संख्या में कमी होना और दूध उत्पादन में कमी। यह पहला सूचना का विषय था। मैं यह बताना चाहूंगा कि विश्व में दूध उत्पादन में भारत 1998 से पहले नम्बर पर है। माननीय वीरेन्द्र जी लोक सभा में थे जब माननीय अटल जी की सरकार थी। भारत वर्ष में दूध के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले वर्ष दूध उत्पादन 137.97 मिलियन टन हुआ था। दुधारू पशुओं की संख्या में भी गिरावट नहीं हुई है। दुधारू पशुओं की अनुमानित संख्या वर्ष 2010-11 में 7.98 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 8.31 करोड़ हो गई। अलग-अलग वैराइटी के विषय में बताएं तो वर्ष 2010-11 में विदेशी गाय 1 करोड़ 18 लाख थीं। देसी गाय 3 करोड़ 9 लाख, भैंस 3 करोड़ 71 लाख कुल 7 करोड़ 78 लाख दुधारू पशु देश में थे। आज स्थिति यह है कि विदेशी गाय 1 करोड़ 26 लाख, देसी गाय 3 करोड़ 19 लाख, भैंस 3 करोड़ 86 लाख और कुल 8 करोड़ 31 लाख है। वर्ष 2010-11 की तुलना में हमारे पास 1 करोड़ 31 लाख ज्यादा दुधारू पशु हैं। इसी तरह से अभी चर्चा हुई कि प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता। दूध ही एक ऐसा क्षेत्र है, जहां वर्ष 1950-51 से ले कर आज तक हमारा ग्राफ़ लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। मार्च, 1950 से फरवरी, 1951 में दूध उत्पादन 17 मिलियन टन था और प्रति व्यक्ति उपलब्धता 120 ग्राम की थी। इसी प्रकार वर्ष 2003-04 में दूध उत्पादन 88 मिलियन टन और प्रति व्यक्ति उपलब्धता 225 प्रति ग्राम थी। वर्ष 2011-12 में दूध उत्पादन 187.9 मिलियन टन और प्रति व्यक्ति उपलब्धता 290 ग्राम प्रति व्यक्ति थी और वर्ष 2013-14 में कुल दूध उत्पादन 137.97 मिलियन टन और प्रति व्यक्ति उपलब्धता 305 ग्राम है। हम इसमें बढ़ रहे हैं, लेकिन यह बात सही है कि जहां दूध की नदियां बहती थीं, उस दूध में प्रगति की रफ्तार पर्याप्त नहीं है, मैं इससे सहमत हूं।...(व्यवधान)

महोदय, दूसरा विषय दूध की कीमत के निर्धारण का है। मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि देश के कुल दूध उत्पादन का 52 प्रतिशत कृषक अपने ही गांव में उपभोग करता है। मिल्क के उत्पादन का 50 परसेंट से ज्यादा हम खुद अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। उत्पादन का लगभग दस प्रतिशत शहरी उपभोक्ताओं को प्रायः सहकारी संस्थाओं द्वारा सुधा, अमूल, मदर डेयरी के द्वारा शहरों में उपलब्ध कराया जाता है। देश में भारतीय उपभोक्ता के लिए कृषक द्वारा दूध की खरीद का जो मूल्य तय होता है, वह भारत सरकार तय नहीं करती है। यह सहकारी क्षेत्र का मामला है। अमूल मॉडल पर आधारित सहकारी संगठनों एवं यूनियन द्वारा की जाती है। इस मॉडल के तहत सहकारी संगठन में दुग्ध को-ऑपरेटिव से जुड़े प्रत्येक कृषक लाभ का भागीदार है एवं दूध की बिक्री के प्रत्येक रुपये पर तकरीबन 80 पैसे किसान को ही मिलते हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब भी कभी दूध की दरें बढ़ती हैं तो उसका मूलतः कारण किसान द्वारा पशु-मवेशी पर दूध उत्पादन में की गयी लागत है, जैसे कि इस वर्ष में मई, 2013 से मई, 2014 तक तीन-चार बार दूध के दाम बढ़े हैं। यह दाम 14.50 प्रतिशत उपभोक्ता के लिए बढ़े हैं, लेकिन किसान का लाभ 17.88 परसेंट बढ़ा है, मतलब मार्किट में जो दाम बढ़ा है सहकारी समितियों के द्वारा किसान का जो लागत मूल्य बढ़ाया जाता है, उसके कारण दूध के दाम बढ़ते हैं।

18.00 hrs.

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, it is now 6

o'clock. If the House agrees, then we can extend the time of House till the reply of the hon. Minister and Zero Hour is over.

SEVERAL HON. MEMBERS: Sir, yes.

श्री राधा मोहन सिंह : सभापति जी, जो उपभोक्ता मूल्य बढ़ता है, उससे ज्यादा खरीद मूल्य बढ़ता है। सहकारी संस्थाएं दाम तय करती हैं, उसी दाम को सबको मानना आवश्यक है। लेकिन जो प्राइवेट डेयरी है क्योंकि, अभी 52 प्रतिशत हम खुद उत्पादन करते हैं, उसमें 10 प्रतिशत सहकारी संस्थाओं का भी होता है, इसलिए यह कुल 62 प्रतिशत बनता है और शेष जो बचता है, जो प्राइवेट डेयरी वाले हैं, वे निर्धारित दर पर नहीं खरीदते होंगे। सबसे ज्यादा परेशानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, जहां सहकारी दुग्ध उत्पादन संस्थाओं का विकास-विस्तार नहीं हुआ है। बिहार का जो पश्चिमी बिहार है,...(व्यवधान) निश्चित रूप से जो 52 प्रतिशत अपना उत्पादन करते हैं, 10 प्रतिशत सहकारी संगठनों से आता है और जो मूल्य तय होता है, उस आधार पर दस प्रतिशत प्राइवेट डेयरी वाले खरीदते हैं। इसके अलावा 28 प्रतिशत असंगठित क्षेत्रों में खरीदारी होती है। असंगठित क्षेत्रों में यानी आपके गांवों के लोग बाजार में ले जाते हैं या रामकृपाल जी जैसे लोग दूध खरीदकर बाजार में ले जाते हैं। अब वे किस दाम पर खरीदते हैं? खरीद का दाम वह होना चाहिए जो सहकारी संगठन खरीदता है।

कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों में डेयरी में ये सारे विषय शामिल हैं लेकिन यह विषय राज्यों का है, यह बात हम सभी जानते हैं। इसके बावजूद भी पशु-पालन, डेयरी, और मत्स्य पालन विभाग, जो भारत सरकार का विभाग है, वह राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। हमारी ड्यूटी उसको वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि पशुओं के दूध के उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोत्तरी हो सके। दूध उत्पादन की बढ़ोतरी का मार्केट पर सकारात्मक असर होना स्वाभाविक है। यह मंत्रालय डेयरी किसानों को सहायता भी प्रदान करता है।

सहायता की बात आई तो मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। केवल किसानों को आयोजित मार्केट तक पर्याप्त दर पर दूध बेचने हेतु पहुंचाने में भी मदद करता है। इसके अतिरिक्त दूध की जो प्रोसैसिंग और मार्केटिंग होती है, इसके लिए भी सरकारी संस्थाओं को हमारा मंत्रालय सहायता प्रदान करता है। देश में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 12वीं योजना के दौरान निम्नलिखित विभागीय योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इससे दूध की कीमतों को स्थिर करने में योगदान मिलेगा, जो भारत सरकार का कार्यक्रम है। उसमें पहला कार्यक्रम राष्ट्रीय बोवाइन और डेयरी विकास कार्यक्रम है। इसमें 12वीं योजना के अंतर्गत 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसमें से विदेशी नस्ल के दुधारू पशुओं के बारे में तो सबको पता है कि इस देश के अंदर 17 प्रतिशत विदेशी नस्ल की गाय हैं और 83 प्रतिशत देशी नस्ल की गाय हैं। हम अपनी योजना के अन्तर्गत इस पर काफी खर्च कर रहे हैं। 17 प्रतिशत गायों के दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करते हैं। उसमें हम कहीं भी कंजूसी नहीं करने वाले हैं, लेकिन 83 प्रतिशत गायों का दूध बढ़े, उनके प्रजनन में सुधार हो, इसके लिए हमारी सरकार ने एक नया मिशन भी चलाया है जिसका नाम राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए की राशि अलग से निकाली गई है ताकि मुख्य रूप से देसी पशुओं के नस्ल सुधार और दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी की जाए। इसी प्रकार से राष्ट्रीय डेयरी योजना के अंतर्गत 2242 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तीसरी योजना डेयरी उद्यमीयता विकास योजना है जिसमें 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा मैं सदन को बताना चाहता हूं कि दुग्ध उत्पादन देश में और बढ़े, यह जिस तेजी से बढ़ना चाहिए, इसकी गति वैसी नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत से देशों के अंदर नेशनल ब्रीडिंग सैंटर है, जो अब्रेला का काम करता है और उसके नीचे बाकी सारे केंद्र हैं। इस देश में ब्रीडिंग सैंटर हैं लेकिन अब्रेला नहीं है। इस देश में नेशनल ब्रीडिंग सैंटर नाम की कोई चिड़िया नहीं है। अभी जब यह सरकार आई है तो हमने अलग से इस वित्तीय वर्ष के लिए इसमें 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल ब्रीडिंग सैंटर की स्थापना की जाए।

महोदय, कुछ और विषय आए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि चारे के उत्पादन के लिए भी पंचवर्षीय योजना में इस बार 400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यह भी दुग्ध उत्पादन में राज्य सहायता का विषय है। फीड प्लांट लगाने के लिए एन.पी.बी.बी., डी.डी.पी. स्कीम में आर.के.वी.वाई. (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) के तहत हम राज्य सरकारों के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर सहायता देते हैं। डेयरी

उद्यमीयता योजना के अंतर्गत 25 प्रतिशत सामान्य वर्ग के लिए, 33 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सब्सिडी का प्रावधान रखा है। मैंने बताया कि यह राज्य का विषय है और हम राज्य के माध्यम से इसे करते हैं। एक दूसरा विषय है कि यहां से पैसे जाते हैं, ठीक है कि उसका बहुत असर नहीं पड़ता होगा, लेकिन कुछ असर पड़ता है। दूध ऐसा क्षेत्र है, जिसमें हम देश में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे एक मित्र ने कहा कि सरकार ने दुग्ध उत्पादन के लिए कोई प्रयास नहीं किया। मैं समझता हूं कि आप जिस पक्ष में बैठे हैं।...(व्यवधान)

श्री राजीव सातव : मैंने ऐसा नहीं कहा, आप रिकॉर्ड चैक कर कीजिए।...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह: राजीव जी, आपने कहा दूध इंडस्ट्री पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। यह आपके शब्द

हैं कि दूध इंडस्ट्री पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया।...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, दूध इंडस्ट्री नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह: वीरेंद्र जी, आप तीसरा विषय क्यों लाते हैं?...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं एक बात और पूछंगा। आपके पास दुधारु पशुओं का जो आंकड़ा अधिकारियों ने दिया है उसे चैक कर लें।...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह: जब मेरा भाषण समाप्त होगा तब पूछिएगा। मेरे मित्र ने कहा है, अब मैं नाम नहीं लूंगा।

SHRI RAJEEV SATAV: Please do not change my words. I have not used that word....(*Interruptions*)

श्री राधा मोहन सिंह: सत्ताधारी दल के मित्र ने कहा कि दूध इंडस्ट्री पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं सहमत हूं कि जितना ध्यान देना चाहिए, उतना ध्यान नहीं दिया। यदि ध्यान न दिया होता तो लगातार दूध के क्षेत्र में देश में बढ़ोतरी हो रही है, वह नहीं होती। पिछले वर्षों में, भले शासन किसी का रहा हो, उस दरम्यान भी बढ़ोतरी हुई है, चाहे स्पीड 100 किलोमीटर की न रही हो, 40 किलोमीटर रही हो, सरकार ने ध्यान दिया होगा। भले ही हमारी विरोधी सरकार थी। सरकार ने यदि काम किया है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि सरकार ने कोई प्रयत्न किया है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए।...(व्यवधान) हमारे पास जितनी बड़ी संख्या में पशुधन है, इस मामले में हमारे पास जितनी आधारभूत संरचना है, दूध उत्पादन करने वाले पशु हैं, मैं इससे सहमत हूं कि जिस स्पीड में उत्पादन बढ़ना चाहिए था, इसलिए मैंने चर्चा की कि 83 प्रतिशत गायों की उपेक्षा की गई। सरकार के ध्यान में है कि इस देश की लाइफ लाइन दुधारु पशु हैं, देश की जीवन रेखा है इसलिए इस देश को तेजी से बढ़ाने का सरकार का संकल्प है।

जहां तक मिलावटी, नकली दूध की बात है, मैं उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि नकली दूध का जो विषय है, वह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का विषय है। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Mr. Minister, you please address the Chair.

श्री राधा मोहन सिंह : यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथारिटी ऑफ इंडिया का मामला है, मैं बात करूंगा, लेकिन इसका सीधा संबंध हमारे मंत्रालय से नहीं है। मैं सदस्यों की इस भावना से सहमत हूं और सरकार भी सहमत है कि दूध उत्पादन में तेजी आनी चाहिए और इसीलिए सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन लांच किया है और इसके लिए काफी धनराशि भी आवंटित की है।

HON. CHAIRPERSON: Now, the House will take up 'Zero Hour'.